

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा के माह 02/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी; श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 05.05.2017 से 18.05.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वजयपाल सिंह नेगी, लेखापरीक्षक एवं श्री वनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 29.02.2016 से 17.03.2016 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 01/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अ धकार क्षेत्र:- जनपद अल्मोड़ा में स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं च कत्सालय मुख्य च कत्सा अ धकारी कार्यालय के भौगोलिक क्षेत्रा धकार के अंतर्गत आते हैं जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुवधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा कया जाना
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेतर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	582.07	580.99	270.05	267.37
2015-16	489.82	462.47	322.57	300.12
2016-17	342.53	300.71	364.49	333.88

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्ति (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्ति			
व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतिम शेष			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2014-15	RCH Flexipool	240.01	627.69	585.03	282.67
	NRHM Additional ties	147.91	363.22	245.67	265.46
	Immunisation	25.66	64.80	71.72	18.74
2015-16	RCH Flexipool	235.56	520.65	672.31	83.90
	NRHM Additional ties	187.90	302.75	405.22	85.43
	Immunisation	18.74	107.47	81.05	45.16
2016-17	RCH Flexipool	83.91	700.63	673.97	100.57
	NRHM Additional ties	85.45	617.53	473.37	229.61
	Immunisation	35.16	91.41	69.13	57.44

(iii) इकाई को वेतन, औष ध, च कत्सा उपकरण, एवं निर्माण आदि मदों हेतु बजट राज्य स्तर से आवण्टित कया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई को 'अ' श्रेणी में वर्गीकृत कया गया है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

- 1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
- 2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
- 3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
- 4). अपर निदेशक (मुख्य च कत्सा अ धकारी एवं प्रमुख च कत्सा अधीक्षक)
- 5). संयुक्त निदेशक (मुख्य च कत्सा अधीक्षक)
- 6). वरिष्ठ च कत्सा अ धकारी
- 7). च कत्सा अ धकारी ग्रेड- 1 (प्रभारी च कत्सा अ धकारी)

8). च कत्सा अ धकारी सामान्य (च कत्सा अ धकारी)

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा (02.2016) से अप्रैल 2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया था प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर:1- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कटौती न कए जाने के कारण प्राइवेट पार्टनर को रुपया 59.25 लाख का अधिक भुगतान।

मई 2013 में महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहारादून (The Concessioning Authority) द्वारा शील नर्सिंग होम प्राइवेट ल मटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश (Concessionaire) के साथ अल्मोड़ा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौखुटिया के पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शप मोड में संचालन हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए Concession Agreement कया गया था। Concessionaire द्वारा Agreement के Schedule-9 में दर्शाये गए 12 clinical staff एवम 30 paramedical staff की schedule-5 में दर्शायी गयी योग्यता एवम अनुभव के आधार पर नियुक्ति करनी थी। तथा उक्त स्टाफ की उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापित करना था। समस्त स्टाफ द्वारा duty hours की शुरुआत एवम समाप्ती पर उक्त सस्टम में उपस्थिती दर्ज करनी थी। तथा biometric system का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना था ताक आवश्यकता होने पर शासन द्वारा भी उसे देखा जा सके। प्राइवेट पार्टनर को fixed grant (1280 वर्गमीटर हेतु रुपया 1595 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह की दर से रुपया 2041600) एवं variable ग्रांट का भुगतान करना था। यदि Concessionaire शैड्यूल-10 में उल्लिखित KPIs को प्राप्त नहीं करता तो पूर्ण त्रैमास हेतु भुगतान से 6 से 10 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत, 11 से 15 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 40 प्रतिशत की कटौती की जानी थी तथा show cause notice भी जारी करना था। प्राइवेट पार्टनर द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत कए गए देयकों को प्रभारी च कत्सा अधिकारी सामुदायिक केंद्र एवं मुख्य च कत्सा अधिकारी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार जांच करते हुए भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित करना था।

अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क concessionaire द्वारा Agreement होने के तीन वर्ष से अधिक के बाद भी Agreement के Schedule-9 में दर्शाये गए 12 clinical staff में से तीन महत्वपूर्ण पद (Physician, Radiologist and Eye Surgeon) पर लेखापरीक्षा तक अधिकांशतः अनुपस्थित रहे। स्टाफ की उपस्थिती एवं KPIs के पारदर्शक निर्धारण हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापित नहीं कया गया। प्रारम्भ से अब तक क्लिनिकल स्टाफ में 27.81 प्रतिशत से 55.22 प्रतिशत (**Annexure-4**) तक अनुपस्थिति रही। आगे अ भलेखों की जांच में पाया गया क क्लिनिकल स्टाफ में physician, radiologist एवं Eye surgeon प्रारम्भ से ही लगातार अनुपस्थित रहे, जिसके कारण प्रारम्भ से ही अल्ट्रासाउंड एवं ईसीजी नहीं कए गए (**Annexure-1,2&3**) परंतु उक्त च कत्सा उपकरण निष्क्रिय रहने हेतु KPI-4 के अनुसार कोई कटौती नहीं की गयी।

आगे, जांच में पाया गया क सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र, चौखुटिया के शासकीय प्रभारी च कत्सा धकारी एवं मुख्य च कत्सा अ धकारी द्वारा Concessionaire द्वारा प्रस्तुत कए गए देयकों की एग्रीमेंट में दर्शाये गए Key Performance Indicators (KPIs) एवम Incentive Mechanism के framework में दर्शाये गए फॉर्मूले के अनुसार पूर्ण रूप से जांच कए बिना देयकों को भुगतान हेतु महानिदेशक, च कत्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अग्रसारित कया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट पार्टनर को अक्टूबर 2014 से अगस्त 2016 तक उसको देय धनराश से रुपया 59.25 लाख (Annexure-5, Table.2) का अधिक भुगतान कया गया।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य च कत्सा धकारी ने उत्तर दिया क KPIs के अनुसार कटौती न कए जाने के संबंध में संबन्धित प्रभारी च कत्सा धकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा, और यह भी कहा क concessionaire का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी च कत्सा धकारी ही नहीं मुख्य च कत्सा अ धकारी को भी उसके द्वारा प्रस्तुत कए गए देयकों की अनुबंध में दर्शाये गए फोर्मूले के अनुसार जांच कए बिना भुगतान हेतु महानिदेशालय को अग्रसारित कए गया, एवं प्राइवेट पार्टनर द्वारा प्रारम्भ से अनुबंध की समाप्ती तक अनुबंध की शर्त के अनुसार अपेक्षित क्लिनिकल स्टाफ की तैनाती नहीं की जिसके कारण जनता पूर्ण स्वास्थ्य सुवधाओं से वंचित रही फर भी अनुबंध समाप्ति की अनुशंसा बहुत देर से की गयी।

इस प्रकार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कटौती कए जाने एवं समय से संवदा भंग हेतु कार्यवाही कए जाने में वरती गयी शथलता एवं लापरवाही के कारण न क जनसाधारण गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुवधाओं से वांछी रहा बल्कि प्राइवेट पार्टनर को देय धनराश से रुपया 59.25 लाख का अधिक भुगतान भी कया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:-1- रुपया 22.54 लाख का अनिय मत व्यय।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों हेतु जारी वार्षिक अनटायड फंड के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनराश का उपयोग उपकेन्द्र के लघु सुधार, गोपनीयता हेतु पर्दे, टैप मरम्मत, वद्युत बल्ब, प्रसव के उपरांत सफाई हेतु तदर्थ भुगतान, एवं बेंडेज, ब्ली चंग पाउडर की अधपरपति में व्यय किया जाएगा। अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनराश का उपयोग किसी प्रकार के वेतन, वाहन अधप्राप्ति एवं आवर्ती व्यय में नहीं किया जाएगा। अभलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मुख्य चकत्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा जनपद के सभी उपकेन्द्रों पर तैनात ANMs द्वारा वत्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मोबाइल रीचार्ज पर आवर्ती रूप से रुपया 200/ प्रति माह की दर से अनटायड फंड के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रुपया 22.54 लाख का अनिय मत व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य चकत्सा अधिकारी ने उत्तर दिया कि मशन निदेशक से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मोबाइल रीचार्ज करने के निर्देश दिये गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मोबाइल रीचार्ज पर आवर्ती रूप से व्यय किया जाना भारत सरकार द्वारा अनटायड फंड के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन था।

अतः अनटायड फंड से रुपया 22.54 लाख के अनिय मत उपयोग का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:-2- रुपया 21.77 लाख की हानि।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु च कत्सालय, बीमा कंपनी तथा TPA के साथ कए गए सेवा अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड च कत्सालय द्वारा लाभार्थी के च कत्सालय से डस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की च कत्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर दिये जाने चाहिए। च कत्सालय द्वारा नेट कनेक्टि वटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अधिकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मैन्युयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देने चाहिए। च कत्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सूचत करेगा, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत कए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी क दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। मुख्य च कत्सा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अभलेखों की संवीक्षा में पाया गया क मई 2017 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत कए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा क्रमशः रुपया 9.36 लाख तथा 12.41 लाख के भुगतान दावे अस्वीकार कए गए, जिसके परिणाम स्वरूप शासन को रुपए 21.77 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अधिकारी ने उत्तर दिया क वलम्ब से दावा प्रस्तुत करने वाले च कत्सालयों को समय-समय पर चेतावनी पत्र जारी कए गए थे, एवं बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कए गए दावों में इंगत क मयों के निराकरण हेतु निर्देशित करते हुए बीमा कंपनी को उक्त दावों का रि व्यू कए जाने हेतु लखा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यदि अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी दावे वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत कए गए होते तो उक्त रुपए 21.77 लाख की हानी को बचाया जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:-3- रुपया 6.36 लाख का अनिय मत व्यय।

भारत सरकार द्वारा RCH Training हेतु जारी Financial Norms के अनुसार जनपद स्तर पर आयोजित आवासीय प्र शक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभा गयो पर (breakfast, working Tea, lunch and dinner) हेतु प्रति दिन अधकतम रुपया 250/ व्यय कया जाना चाहिए। अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क फ़रवरी 2016 से मार्च 2017 तक जनपद स्तर पर आयोजित अनावासीय प्र शक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले का र्मकों को भोजन उपलब्ध कराने पर रुपया 6.36 लाख का व्यय कया गया।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अधकारी ने उत्तर दिया क भ वष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वतीय मानकों के अनुसार व्यय कया जाएगा।

STAN

प्रस्तर:- 1- धनराश रु 2,43,129/- के निष्प्रयोज्य वाहनों का नीलामी न कया जाना

कार्यालय मुख्य चकत्सा अधिकारी, अल्मोड़ा में वर्ष 2007 से 2014 के मध्य धनराश रु 2,43,129/- के कुल सात वाहन आफ रोड घोषित कये गए थे, जिनकी नीलामी होनी अभी तक लम्बित थी नीलामी न कये जाने के कारण उक्त वाहनों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त वाहनों के नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी

लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर मुख्य चकत्सा अधिकारी, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया क वाहनों की नीलामी हेतु दो बार वज्रपति प्रकाशत होने के उपरान्त भी कसी निवदा दाता द्वारा प्रतिभाग न कये जाने के कारण नीलामी नहीं की जा सकी उत्तर स्वीकार्य नहीं है आफ रोड घोषित कये जाने के 3 से 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी नीलामी नहीं की गयी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर:-2-धनरा श रु 133.61 लाख का अवरोधन।

जिला योजना के अंतर्गत राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछीना के मुख्य भवन, टाइप-4 के एक आवास, टाइप-2 के एक एवं टाइप-1 के दो आवासों के निर्माण हेतु (फरवरी 2015), एवं उपकेंद्र गुदलेख के मुख्य भवन के निर्माण (फरवरी 2016) हेतु क्रमशः रुपया 99.81 लाख, तथा 33.80 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष कार्यदायी संस्था पेयजल निगम, रानीखेत को उक्त कार्यों हेतु क्रमशः रुपया 99.81 लाख, तथा रुपया 33.80 लाख की धनरा श क्रमशः फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 में अवमुक्त की जा चुकी थी। अभलेखों की जांच में पाया गया क राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछीना एवं उपकेन्द्र गुदलेख के मुख्य भवन का निर्माण कार्य मुख्य च कत्सा अधकारी कार्यालय द्वारा निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को भूम उपलब्ध न कराये जाने के कारण स्वीकृति के एक से दो वर्ष बाद तक भी आरंभ नहीं कया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्था के पास उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त रुपया 133.61 लाख की धनरा श लगभग एक से दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य च कत्सा अधकारी ने उत्तर दिया क राजकीय एलोपै थक च कत्सालय कनारीछीना में पूर्व भूम ववादित होने के कारण पुनः भूम चन्हित कर हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है एवं उपकेन्द्र गुदलेख हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गयी भूम, उपयुक्त न होने के कारण पुनः भूम उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धनरा श अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों हेतु निर्ववादित एवं उपयुक्त भूम का हस्तांतरण सुनिश्चित कया जाना चाहिए था, ता क कार्य समय से आरंभ कया जा सकता। परन्तु, मुख्य च कत्सा अधकारी कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों हेतु निर्ववादित एवं उपयुक्त भूम उपलब्ध न कराये जाने में बरती गयी शथलता के कारण उक्त कार्य स्वीकृति के पंद्रह से सताईस माह बाद भी आरंभ नहीं कए जा सके थे, एवं रुपया 133.61 लाख क धनरा श कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-3- स्वीकृति के पन्द्रह वर्षों बाद भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी कार्यों की भौतिक प्रगति आख्या के अनुसार शासन द्वारा राज्य एवं जिला योजना के अंतर्गत मार्च 2002 से अप्रैल 2013 तक बारह निर्माण कार्यों हेतु रुपया 14.43 करोड़ की वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यों में से पाँच कार्य कार्यदाई संस्था आर0ई0एस0 को, छह कार्य पेयजल निगम को एवं एक कार्य उ0प्र रा0 निर्माण निगम को आबंटित कये गये थे। कार्यदाई संस्थाओं को स्वीकृत धनराश के सापेक्ष मार्च 2017 तक रुपया 11.90 करोड़ की धनराश अवमुक्त की जा चुकी थी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रुपया 10.93 करोड़ की धनराश व्यय की जा चुकी थी एवं रुपया 0.97 करोड़ की धनराश कार्यदायी संस्थाओं के पास अवशेष पड़ी हुई थी (अनुलग्नक-1)।

आगे, अभलेखों की जांच में पाया गया क उक्त कार्यों में से चार कार्यों हेतु रुपया 2.96 करोड़ की लागत वृद्ध के साथ शासन को सतंबर 2014 में पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित कए गए थे, जो आतिथ तक शासन द्वारा स्वीकृत नहीं कए गए थे। इस प्रकार वभागीय उदासीनता के कारण स्वीकृति के चार से 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।

लेखापरीक्षा में इंगत कए जाने पर मुख्य चकत्सा अधिकारी ने उत्तर दिया क कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत धनराश एकमुश्त अवमुक्त न कए जाने के कारण, प्रतिवर्ष अनुसूची दरों में वृद्ध होने के कारण लागत में वृद्ध होने से एवं निर्माण कार्यों हेतु भूम उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य चकत्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्माण कार्यों हेतु धनराश अवमुक्त करने से पूर्व भूम क उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी तथा निर्माण कार्यों के व भन्न भागों हेतु चरणवद्ध तरीके से प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्यदायी संस्था के साथ कार्य पूर्ण करने की तिथ निर्धारित करते हुए अनुबंध गठित कर स्वीकृत धनराश एकमुश्त अवमुक्त की जानी चाहिए थी, ता क कार्यों को समय से पूर्ण कया जा सकता एवं लागत वृद्ध से बचा जा सकता। परंतु, मुख्य चकत्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त कार्यों के निष्पादन में वरती गयी शथलता के कारण उक्त कार्य स्वीकृति के पन्द्रह वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं कए गए थे एवं प्रेषित पुनरीक्षित आगणनों के अनुसार सतंबर 2014 तक रुपया 2.96 करोड़ की लागत वृद्ध हो चुकी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
सा.क्षे. AIR/106/2008-09	2	3	शून्य	शून्य
सा.क्षे. AIR/35/2010-11	1	1 to 6	शून्य	शून्य
सा.क्षे. AIR/73/2011-12	1	1 to 3	शून्य	शून्य
सा.क्षे. AIR/122/2013-14	1	1 to 2	शून्य	शून्य
सा.क्षे. AIR/219/2015-16	01	1 to 7	शून्य	1, 2 & 3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे. AIR/106/2008-09	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 2 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 3	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	---
सा.क्षे. AIR/35/2010-11	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 6	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	---
सा.क्षे. AIR/73/2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 3	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	---
सा.क्षे. AIR/122/2013-14	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	---
सा.क्षे. AIR/219/2015-16	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 से 7 एवं - 1 से 3	संलग्न है	यथावत रखा जाता है	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य

भाग-Vआभार

- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चकत्सा अधिकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

- सतत अनियमितताएं:
 - शून्य
- लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	पदनाम	अवध
डॉ० रमेश चन्द्र पन्त	मुख्य चकत्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चकत्सा अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी- 1/05, वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र

